



2026:AHC:125765-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23209 वर्ष 2026

काव्यांश सिंह..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : तेजस सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., गौरव कुमार चंद

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

1. मौखिक प्रार्थना पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिन के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, लखनऊ को पक्षकार प्रतिपक्षी संख्या-4 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. पक्षों के अधिवक्ता को सुना।
3. याचिकाकर्ता पासपोर्ट जारी करने के लिए उसके आवेदन के लंबित होने से व्यथित है।
4. प्रस्तुत मामले के तथ्य रिट-सी संख्या-41540 वर्ष 2023 (पवन कुमार राजभर बनाम भारत संघ और 2 अन्य) के समान हैं। उस रिट याचिका का दिनांक 19.01.2024 के आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों में निस्तारण किया गया है:

"26. पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के लिए मौजूदा फॉर्म के भाग ए के प्रस्तर-2 में लिखा है:

"2. क्या आवेदक किसी भी अदालत में किसी आपराधिक आरोप का सामना कर रहा है?

हां/ नहीं

(यदि हाँ, तो कृपया आपराधिक मामले का विशिष्ट विवरण प्रदान करें)"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस प्रकार, उपरोक्त को लागू करने के तौर-तरीकों के रूप में, जैसा कि श्री ए.के. सैंड, विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया है, अब से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत की गई सभी पुलिस रिपोर्टों में उपरोक्त क्षेत्र के खिलाफ वांछित / प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:

(1) पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुत) के भाग 'क' में, मद '2' के खिलाफ, कुछ समय के लिए, उन सभी मामलों में विकल्प 'हां' का चयन किया जा सकता है जहां आवेदक के खिलाफ एन.सी.आर. और/या प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। दूसरा, उस क्षेत्र में (जिसे तब सक्रिय किया जा सकता है), ऐसे एन.सी.आर. और/या प्राथमिकी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर दिया जा सकता है:

एन.सी.आर. सं ; थाना-.....

और/या

प्राथमिकी सं ; यू / एस (अनुभाग विवरण);

थाना-(थाना का विवरण), न्यायालय के तहत (न्यायालय का विवरण)

.....

27. उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने पर, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे:

(1) ऐसी न्यूनतम सूचना व्यक्तिगत आवेदक को दिखाई देने वाले अपने वेब पोर्टल पर अपलोड की गई है। इसके अलावा, जब भी कोई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, तो वह वेब पोर्टल आवेदक को आवेदन करने और उसके आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने का संकेत देगा।

(2) उस जानकारी को पहले की तरह एक ठोस नोटिस जारी करके आवेदक को भी सूचित किया जा सकता है।



(3) भारत संघ/प्रतिपक्षी संख्या-1 अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत कर सकता है ताकि

(i) आवेदक को अपने मोबाइल फोन पर उचित संदेश के माध्यम से इस तरह के नोटिस की सूचना भेजना सुनिश्चित किया जा सके, जहां भी ऐसे विवरण उपलब्ध हों।

(ii) संपूर्ण सूचना को अपने वेब पोर्टल पर अपलोड करें। सुशासन की मांग इस तरह के कदम को तेजी से उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जैसा कि राजकोषीय कानूनों के मामले में पहले ही किया जा चुका है।

(4) जैसा कि ए.एस.जी.आई. द्वारा उचित रूप से कहा गया है, ऐसे मामलों में जहां कोई एन.सी.आर. पंजीकृत किया जा सकता है, आवश्यक पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, पुनः जारी किया जा सकता है, नवीकृत किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, बिना किसी देरी के। उन मामलों में आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय से कोई अनुमति नहीं मांगी जा सकती है या इसकी आवश्यकता नहीं होती है।

28. आपराधिक क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय में आवेदन करने के लिए आवेदक द्वारा आवश्यक समय और इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, उत्तर प्रदेश यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने की सूचना आवेदक के साथ जल्द से जल्द यानी संबंधित राज्य प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर साझा की जाए। इसके बाद, संबंधित आवेदक को उस अनुमति को प्राप्त करने और तदनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को सूचित करने के लिए कम से कम आठ सप्ताह का पर्याप्त समय दिया जा सकता है। उस अवधि के दौरान उसका आवेदन लंबित रखा जा सकता है। एक बार देय अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह से अधिक समय तक पासपोर्ट जारी करने, पुनः जारी करने, नवीकरण करने में विलंब नहीं कर सकता है।

29. आगे के प्रविधि को अपनाने के लिए हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और इसे क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और राज्य अधिकारियों पर छोड़ते हैं कि वे कानून के अनुसार कार्य करना जारी रखें। इस संबंध में, हमें अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों से अवगत कराया गया है जिसमें प्रक्रियाओं में गहन संशोधन की



आवश्यकता है। वर्तमान आदेश में ऐसे किसी भी आदेश को जोड़ने या संशोधित करने का प्रयास नहीं किया गया है। हम केवल मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत दक्षता सुनिश्चित करना चाहते हैं।

30. अंत में हम स्पष्ट करते हैं कि ये निर्देश बासू यादव (उपरोक्त) के मामले में जारी किए गए किसी भी निर्देश के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं बल्कि इसके अलावा जारी किए गए हैं।

31. जहां तक प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं का संबंध है, हम राज्य अधिकारियों से इन निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर नई सूचना भेजने की अपेक्षा करते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय इन निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं को लिखित रूप में आवश्यक संचार जारी करेगा।

32. चूंकि सभी व्यक्तिगत आवेदकों को दो महीने का समय दिया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से सूचना प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर संबंधित न्यायालय में आवेदन करने के अधीन, हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित न्यायालय उसके बाद चार सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे। हालांकि, तात्कालिकता से जुड़े मामलों में, उन आदेशों को तेजी से किया जा सकता है, जो उद्धृत तात्कालिकता के अनुरूप हों।

5. समान तथ्यों और समान तर्क के आधार पर, प्रस्तुत याचिका का भी निस्तारण समान नियमों और शर्तों पर किया जाता है।

5 जून 2026 / केपीवाई

(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)

(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)